Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

27 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 15 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) पर PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए IPSrC की 755 परियोजनाओं को 77.98 करोड़ रुपये जारी

PIB backgrounder on Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY): Rs 77.98 crore released to 755 IPSrC projects for the quarter ending 30 September 2026

SSC • Railway • General

PIB की 27 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी (बैकग्राउंडर) में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की व्यापक योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), का विवरण दिया गया है। वर्ष 2021 में शुरू की गई इस योजना ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC) को अपने में समाहित कर उसका विस्तार किया; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से लागू करता है। पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) घटक के अंतर्गत 755 परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में 77.98 करोड़ रुपये जारी किए। मुख्य कार्यान्वयन घटक IPSrC गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान देता है, और वर्तमान में 764 वरिष्ठ नागरिक गृहों, 13 सतत देखभाल केंद्रों, 17 सचल चिकित्सा इकाइयों और 3 फिज़ियोथेरेपी क्लिनिकों को सहायता दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC) के तहत राज्य अपने आवंटित धन का 20% तक राज्य-विशेष कार्यक्रमों पर ख़र्च कर सकते हैं। वर्ष 2017 में एक स्वतंत्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू हुई और बाद में AVYAY में शामिल की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना से 10.45 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का लाभ मिला है, और अक्टूबर 2021 में शुरू हुई वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) को 8.66 लाख से अधिक ऐसी कॉल मिली हैं जिन पर कार्रवाई की गई। पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार, जनगणना 2011 के मुताबिक़ देश में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) थे, और 2036 तक वृद्धजनों की संख्या 23 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328814

2 कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) पर PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: केंद्रीय बजट 2026-27 की CCUS योजना में पाँच वर्षों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित

PIB backgrounder on Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS): Rs 20,000 crore over five years for CCUS under the Union Budget 2026-27 CCUS Scheme

SSC • Railway • Environment • General

PIB की 27 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) - औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में पहुँचने से पहले पकड़ना और फिर उसका उत्पादक उपयोग करना या उसे ज़मीन के नीचे सुरक्षित रूप से भंडारित करना - को उत्सर्जन कम करने में कठिन (हार्ड-टू-एबेट) क्षेत्रों का उत्सर्जन घटाने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम और भारत के वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य में सहायक बताया गया है। नीति आयोग इस्पात, सीमेंट, तेल एवं गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और उर्वरक क्षेत्रों के डीकार्बोनाइज़ेशन के लिए CCUS को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानता है; पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों और ताप विद्युत उत्पादन से होने वाला उत्सर्जन 2030 तक लगभग 2,300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुँचने का अनुमान है, और अगस्त 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 45.12% थी। कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, यूरिया, ग्रीन मेथनॉल और कंक्रीट में किया जा सकता है, या उसे ख़ाली हो चुके तेल एवं गैस भंडारों, गहरे खारे जलभृतों और बेसाल्ट चट्टान संरचनाओं में स्थायी रूप से भंडारित किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का CCUS रोडमैप 2025 क्लस्टरों के लिए गुजरात तट, ओडिशा-झारखंड बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत जैसे संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है। पृष्ठभूमि टिप्पणी में फ़रवरी 2026 में केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित CCUS योजना का उल्लेख है, जिसके तहत वित्त मंत्रालय ने पाँच क्षेत्रों - बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफ़ाइनरी और रसायन - में CCUS के लिए पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए; साथ ही नीति आयोग की CCUS नीति रूपरेखा रिपोर्ट (नवंबर 2022), 2022 में आईआईटी बॉम्बे और जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु में स्थापित राष्ट्रीय CCUS केंद्रों, और मई 2026 में आईआईटी बॉम्बे में उद्घाटित भारत की पहली एकीकृत CCUS फ़ील्ड प्रयोगशाला का उल्लेख है, जो प्रतिदिन 3 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकती है। अप्रैल 2026 तक तीन CCU परियोजनाएँ संचालित थीं, छह निर्माणाधीन या कार्यान्वयन के चरण में थीं और सोलह प्रस्तावित चरण में थीं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328830

3 केंद्रीय सतर्कता आयोग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 मना रहा है

CVC observes Vigilance Awareness Week 2026 from 26 October to 1 November on the theme 'Probity for Prosperity'

SSC • Banking • General

27 अक्टूबर 2026 की एक रिलीज़ के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' (Probity for Prosperity) विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 मना रहा है। सप्ताह की शुरुआत नई दिल्ली के सतर्कता भवन में सुबह 11 बजे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ए. एस. राजीव और सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ द्वारा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के साथ हुई। आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को 17 अगस्त से 16 नवंबर 2026 तक तीन माह का निवारक सतर्कता अभियान चलाने की भी सलाह दी है, जिसमें लंबित शिकायतों का निपटान, लंबित मामलों का निपटान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, डिजिटल पहल और अनुबंध प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सप्ताह के अंतर्गत आयोग ने 30 अक्टूबर 2026 को 'प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन' (Transformation Through Technology) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328846

4 DPIIT: 2,50,046 स्टार्टअप को मान्यता; स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर अब 20 करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये से दोगुना)

DPIIT: 2,50,046 startups recognised; guarantee cover per borrower under the Credit Guarantee Scheme for Startups now Rs 20 crore (doubled from Rs 10 crore)

SSC • Banking • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि उसने अनुमति-आधारित नियामक ढाँचे से विश्वास-आधारित नियामक ढाँचे की ओर निरंतर बदलाव किया है। DPIIT ने 2,50,046 स्टार्टअप को मान्यता दी है, जिन्होंने 770 से अधिक ज़िलों और 56 उद्योगों में 25.42 लाख से अधिक रोज़गार की जानकारी दी है; इनमें से 52% स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों से हैं और 48% में कम से कम एक महिला निदेशक है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1,662.71 करोड़ रुपये के 532 ऋणों की गारंटी दी गई है; प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से दोगुना करके 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है, और 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए वार्षिक शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है। एंजल टैक्स की समाप्ति सहित कुल 63 नियामक सुधार किए गए हैं; केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 47,957 अनुपालन घटाए गए हैं; और जन विश्वास अधिनियमों ने केंद्रीय क़ानूनों के 900 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है - 2023 में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान और 2026 में 79 अधिनियमों के 717 प्रावधान। उनतीस केंद्रीय श्रम क़ानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है। भारत को वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 843 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला, और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.53 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक निवेश प्रवाह रहा। सितंबर 2021 में सॉफ़्ट लॉन्च हुई राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) पर अब 3,779 सेवाएँ उपलब्ध हैं और यह 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328842

5 आर्मेनिया के येरेवन में CBD COP-17 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य: मंत्री ने कहा, भारत की अद्यतन NBSAP वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों और 142 संकेतकों में रूपांतरित करती है

India's National Statement at CBD COP-17 in Yerevan, Armenia: Minister says India's updated NBSAP translates the Global Biodiversity Framework into 23 national targets and 142 indicators

SSC • Railway • Environment • General

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 27 अक्टूबर 2026 को आर्मेनिया के येरेवन में जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (CBD COP-17) के उच्च-स्तरीय खंड में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) का कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, परिस्थितियों और क़ानूनों के अनुरूप होना चाहिए और उसे विकसित देशों से पर्याप्त और पूर्वानुमेय वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन मिलना चाहिए। भारत कैली फंड सहित बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल अनुक्रम सूचना से होने वाले लाभों के बँटवारे का भी समर्थन करता है, और मंत्री ने संश्लेषित जीवविज्ञान (सिंथेटिक बायोलॉजी) और जैव-सुरक्षा के प्रति विज्ञान-आधारित, जोखिम-अनुपाती और एहतियाती दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने बताया कि भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) GBF को 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों और 142 संकेतकों में रूपांतरित करती है। मंत्री ने कहा कि देश में 1,134 संरक्षित क्षेत्र, 103 रामसर स्थल, 57 जैव विविधता विरासत स्थल और 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के मानव और जैवमंडल नेटवर्क में शामिल हैं; उन्होंने विश्व की सात बड़ी बिल्ली (बिग कैट) प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ा रहे अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस, मिशन लाइफ़ और 'एक पेड़ माँ के नाम', तथा मैंग्रोव पुनर्स्थापन के लिए मिष्टी (MISHTI), आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने क़ानूनों को कन्वेंशन के अनुरूप बनाया है और विकेंद्रीकृत पहुँच एवं लाभ-बँटवारे के लिए ग्राम-स्तरीय समितियाँ स्थापित की हैं, और भारत 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की सच्ची भावना से GBF को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षकारों के साथ काम करता रहेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328896

6 भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 11वां संस्करण इंडोनेशिया के बन्युवांगी में शुरू

11th edition of the India-Indonesia Joint Special Forces Exercise GARUDA SHAKTI begins at Banyuwangi, Indonesia

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास 'गरुड़ शक्ति' का 11वां संस्करण इंडोनेशिया के बन्युवांगी में शुरू हो गया है; यह अभ्यास 27 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक चलेगा। भारतीय सैन्य दल में पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिक शामिल हैं, जबकि इंडोनेशियाई सैन्य दल में इंडोनेशियाई विशेष बल के जवान शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतरक्रियाशीलता को मज़बूत करना है। प्रशिक्षण जंगल के वातावरण में विशेष अभियानों की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, जिनमें बाधा पार करना, लड़ाकू निशानेबाज़ी, पर्वतारोहण, हवाई हमला (एयर असॉल्ट) प्रशिक्षण और युद्ध-कठोरता (कॉम्बैट हार्डनिंग) सत्र शामिल हैं; इसमें हथियारों, उपकरणों और परिचालन पद्धतियों पर विशेषज्ञता और जानकारी का आदान-प्रदान भी शामिल है। संयुक्त प्रशिक्षण का समापन एक सत्यापन अभ्यास से होगा, जिसे वास्तविक परिचालन परिदृश्यों का अनुकरण करने और दोनों दलों की सहनशक्ति, समन्वय और युद्ध तत्परता का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328954

7 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने दक्षिण-पूर्वी अरब सागर से गहरे समुद्र की नई इलेक्ट्रिक रे प्रजाति Tetronarce ramanamurthyi (अरेबियन ब्लैक इलेक्ट्रिक रे) का वर्णन किया

ZSI describes a new deep-sea electric ray, Tetronarce ramanamurthyi (Arabian Black Electric Ray), from the southeastern Arabian Sea

SSC • Railway • Science • General

कोलकाता से 27 अक्टूबर 2026 को जारी एक रिलीज़ के अनुसार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के गहरे जल से इलेक्ट्रिक रे (विद्युत रे मछली) की एक नई प्रजाति, Tetronarce ramanamurthyi, की खोज कर उसका वर्णन किया है। यह उत्तरी हिंद महासागर में Tetronarce वंश (जीनस) का पहला पुष्ट रिकॉर्ड है। यह शोध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन की उस परियोजना के तहत किया गया, जो भारतीय जल में गहरे समुद्र के कॉन्ड्रिक्थियन (उपास्थियुक्त या कार्टिलेजिनस मछलियों) पर केंद्रित है, और निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्गिकी (टैक्सोनॉमी) पत्रिका ज़ूटैक्सा (Zootaxa) में प्रकाशित हुए हैं। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से एकत्र नौ नमूनों के आधार पर वर्णित इस प्रजाति - जिसका सामान्य नाम अरेबियन ब्लैक इलेक्ट्रिक रे है - की पृष्ठीय सतह एकसमान गहरे नीले-काले से गहरे भूरे रंग की है, इसकी डिस्क लंबाई से अधिक चौड़ी है, इसके विद्युत अंग छोटे हैं और कुल कशेरुक संख्या 99 (30 मोनोस्पॉन्डिलस और 69 डिप्लोस्पॉन्डिलस सेंट्रा) है। माइटोकॉन्ड्रियल COI और ND2 जीन की DNA सीक्वेंसिंग ने एक अलग विकासवादी वंशावली के रूप में इसकी पुष्टि की; COI विश्लेषण में आनुवंशिक भिन्नता 2.2% (T. tokionis की तुलना में) से 6.7% (T. nobiliana की तुलना में) तक रही। इस खोज का नेतृत्व चेन्नई स्थित ZSI के समुद्री जीवविज्ञान क्षेत्रीय केंद्र (MBRC) के डॉ. के. के. बिनीश और अनिल काशीनाथ ने, अमेरिका की सैन होज़े स्टेट यूनिवर्सिटी की मॉस लैंडिंग मरीन लेबोरेटरीज़ के पैसिफ़िक शार्क रिसर्च सेंटर के डॉ. डेविड ए. एबर्ट के सहयोग से किया। प्रजाति का नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के मिशन निदेशक डॉ. एम. वी. रमण मूर्ति के सम्मान में रखा गया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328914

8 जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएगा, जिसका समापन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के साथ होगा

Ministry of Tribal Affairs to observe Janjatiya Gaurav Pakhwada from 1 to 15 November 2026, culminating in Janjatiya Gaurav Diwas on Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary

SSC • Railway • General

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि वह 1 से 15 नवंबर 2026 तक देश भर में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएगा, जिसका समापन 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस (JJGD) के साथ होगा। मंत्रालय के अनुसार यह पखवाड़ा उसके प्रमुख कार्यक्रमों में तेज़ी लाने, उनके लाभ अंतिम छोर तक जनजातीय परिवारों तक पहुँचाने और योजनाओं व अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक केंद्रित, समयबद्ध अभियान है। भारत सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया; पिछले 5 वर्षों में यह दिवस रांची (2021), खूंटी (2022 और 2023), जमुई (2024) और डेडियापाड़ा (2025) में मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 2024-25 में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाई गई, जिसमें 28 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और 2 लाख से अधिक गतिविधियाँ हुईं, जिनमें 3.8 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष के लिए तय कार्यक्रमों में 12 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लगभग 200 विद्यार्थियों का राष्ट्रपति से संवाद, 12 और 13 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, और 14 नवंबर को रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सम्मेलन शामिल हैं, जिसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 500 जनजातीय महिला उद्यमी एक साथ आएँगी। जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाएँ शुरू की जानी हैं - 228 उद्घाटन के लिए और 74 शिलान्यास के लिए तैयार हैं। दो राष्ट्रीय डिजिटल पहलें भी शुरू की जानी हैं: ICMR के साथ विकसित जन-हित (जनजातीय स्वास्थ्य इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी) पोर्टल, जिसे मंत्रालय जनजाति-वार स्वास्थ्य आँकड़ों के लिए भारत का पहला प्लेटफ़ॉर्म बताता है, और राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकार दावों की प्रक्रिया को एक ही प्रणाली पर लाएगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328976

9 सितंबर 2026 के ट्राई आँकड़े: 1367.93 मिलियन टेलीफोन ग्राहक; समग्र टेली-घनत्व (एम2एम कनेक्शन सहित) 95.52%

TRAI data for September 2026: 1367.93 million telephone subscribers; overall tele-density (with M2M connections) 95.52%

SSC • Banking • General

संचार मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सितंबर 2026 तक के दूरसंचार सदस्यता आँकड़े जारी किए हैं। सितंबर 2026 के अंत में देश में 1367.93 मिलियन टेलीफोन ग्राहक थे (1319.19 मिलियन वायरलेस और 48.74 मिलियन वायरलाइन); महीने के दौरान 7.23 मिलियन की शुद्ध वृद्धि हुई और मासिक वृद्धि दर 0.53% रही। शहरी टेलीफोन ग्राहक 807.78 मिलियन और ग्रामीण ग्राहक 560.16 मिलियन थे, यानी उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 59.05% और 40.95% रही। समग्र टेली-घनत्व एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शन सहित 95.52% और इनके बिना 85.41% रहा; शहरी टेली-घनत्व 155.85% और ग्रामीण टेली-घनत्व 61.30% था। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शन सहित 1,107.68 मिलियन और इनके बिना 1,013.87 मिलियन थी। सितंबर 2026 में 16.77 मिलियन ग्राहकों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए, और पीक वीएलआर (विज़िटर लोकेशन रजिस्टर) की तिथि पर सक्रिय वायरलेस (मोबाइल) ग्राहकों की संख्या 1212.80 मिलियन थी। ये आँकड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई को दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328945

10 इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ईएसटीआईसी) 2026 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ एक वर्ष में अनुसंधान और विकास के लिए कुल 24 हजार करोड़ रुपये की नई प्रतिबद्धता हुई

At the inauguration of ESTIC 2026, the Prime Minister says a total new commitment of 24 thousand crore rupees was made for Research and Development in just one year

SSC • Railway • Science • General

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ईएसटीआईसी) 2026 के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि दशकों पहले भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब 'कैच अप' यानी पीछे से बराबरी करना था, लेकिन 21वीं सदी का भारत अब नई टेक्नोलॉजी बनाने, उसकी दिशा तय करने और दुनिया की समस्याओं के समाधान देने की शक्ति विकसित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यह उल्लेख करते हुए कि 30 अक्टूबर को देश डॉ. होमी जहांगीर भाभा की जन्मजयंती मनाएगा, उन्होंने कहा कि भारत अपनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम कर रहा है और कुछ महीने पहले ही देश का 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट क्रिटिकैलिटी तक पहुँच चुका है। अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के एक स्पेस स्टार्ट-अप ने मेड इन इंडिया रॉकेट से पहली ही कोशिश में सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया और भारत ने सैटेलाइट डॉकिंग की क्षमता भी हासिल की; उन्होंने यह भी कहा कि इसी वर्ष भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित की और अपना मॉडल भी लॉन्च किया, तथा भारत में तैयार चिप्स के पहले शिपमेंट अब दुनिया तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। यह याद करते हुए कि पिछले वर्ष इसी मंच पर अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था का संकल्प लिया गया था, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में करीब 12 हजार करोड़ रुपये ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए कमिट किए जा चुके हैं जो लैब से निकलकर मार्केट की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, और इसमें निजी निवेशक भी बराबर से साझेदारी कर रहे हैं: सरकार की ओर से 12 हजार करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ निजी क्षेत्र भी 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, यानी सिर्फ एक वर्ष में अनुसंधान और विकास के लिए कुल 24 हजार करोड़ रुपये की नई प्रतिबद्धता हुई है। उन्होंने कहा कि दस वर्ष पहले सालभर में 50 हजार से भी कम पेटेंट आवेदन दाखिल होते थे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या करीब डेढ़ लाख तक पहुँच गई। उन्होंने कुछ दिन पहले आईआईटी मद्रास में अपने द्वारा लोकार्पित ब्रेन सेंटर का उल्लेख किया, जो मानव मस्तिष्क की हाई-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल 3D तस्वीरें विकसित करने में जुटा है; 'जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का आह्वान दोहराया; कहा कि एआई वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सोच को सीमित न करे बल्कि उसे और समृद्ध बनाए तथा जवाब की सत्यता परखने की जिम्मेदारी वैज्ञानिक की ही होनी चाहिए; और कॉन्क्लेव में उपस्थित प्रत्येक शोधकर्ता, उद्योग जगत के अग्रणी, स्टार्ट-अप संस्थापक और युवा विद्यार्थी से आग्रह किया कि वे एक ठोस लक्ष्य तय करें कि अगले तीन वर्षों में वे कौन-सी टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइप, पायलट प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट विकसित करने में योगदान देंगे, ताकि यह कॉन्क्लेव मापने योग्य परिणामों (मेज़रेबल आउटकम्स) का मंच बने।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329161

11 भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिम्बेक्स-2026) का 33वां संस्करण संपन्न

33rd edition of the Singapore-India Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX-2026), hosted by the Indian Navy at Visakhapatnam, concludes

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिम्बेक्स-2026) का 33वां संस्करण 26 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुआ। इस अभ्यास ने भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सहयोग और परिचालन जुड़ाव को और मज़बूत किया। द्विपक्षीय जुड़ाव के हिस्से के रूप में RSN के फ्लीट कमांडर कर्नल बर्ट्रम आंग ने पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई से भेंट की और दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मज़बूत करने पर पेशेवर विचारों का आदान-प्रदान किया। सिम्बेक्स-2026 दो चरणों में आयोजित किया गया: हार्बर चरण में विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEE), क्रॉस-डेक दौरे, पेशेवर संवाद, खेल गतिविधियाँ और योजना सम्मेलन हुए, जबकि बंगाल की खाड़ी में हुए समुद्री चरण में समुद्री अवरोधन अभियान (मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन), पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW), वायु-रोधी युद्ध और सतह-रोधी युद्ध अभ्यास, नौवहन कौशल (सीमैनशिप) अभ्यास और क्रॉस-डेक उड़ान अभियान शामिल थे। RSN का प्रतिनिधित्व आरएसएस सुप्रीम (RSS Supreme) ने किया, जो SH-70B हेलीकॉप्टर से लैस एक फॉर्मिडेबल-श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है, जबकि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरि, पनडुब्बी-रोधी कार्वेट आईएनएस कमोर्टा और P-8I व डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान, हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर तथा MH-60R हेलीकॉप्टर सहित विमानन संसाधनों ने किया। मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329151

12 टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए रियायती स्थानीय पास: 1 नवंबर 2026 से प्रति वर्ष 1,500 रुपये या 3,000 रुपये

Concessional Local Pass for National Highway users living within 20 km of a fee plaza: Rs 1,500 or Rs 3,000 a year, from 1 November 2026

SSC • Railway • General

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए 'रियायती स्थानीय पास' शुरू किया है; मंत्रालय ने इसे टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने ('ईज़ ऑफ़ लिविंग') की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। पास का वार्षिक शुल्क नगर पालिका या स्थानीय शहर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 3,000 रुपये होगा। वैध और चालू फ़ास्ट टैग वाले और 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक किसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा से आवाजाही के लिए मौजूदा मासिक पास और रियायती स्थानीय पास में से किसी एक को चुन सकते हैं; यह पास केवल उसी टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा और किसी अन्य टोल प्लाज़ा पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगा जहाँ टोल शुल्क संग्रह 'क्लोज्ड यूजर-फ्री कलेक्शन सिस्टम' पर आधारित है, और उन स्थानों पर भी जारी नहीं किया जाएगा जहाँ यात्रियों के उपयोग के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है। वार्षिक स्थानीय पास पात्र टोल प्लाज़ा पर 1 नवंबर 2026 से और 'राजमार्गयात्रा ऐप' के माध्यम से 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगा। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, और केंद्र सरकार इन दरों को प्रतिवर्ष संशोधित कर सकती है, जो बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे। देश भर में 13 करोड़ से अधिक फ़ास्ट टैग जारी होने के साथ, इस प्रावधान का उद्देश्य टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले पात्र निवासियों की यात्रा को अधिक किफ़ायती बनाना और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान बनाना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329077

13 डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का 6वां संस्करण (एनएसए 6.0) शुरू किया, 20 क्षेत्रवार और 3 विशेष श्रेणियाँ; आवेदन 27 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक

DPIIT launches the 6th edition of the National Startup Awards (NSA 6.0) with 20 sectoral and 3 special categories; applications open from 27 October to 20 November 2026

SSC • Banking • General

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने नवाचार और उद्यमिता को मान्यता देने तथा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का 6वां संस्करण (एनएसए 6.0) शुरू किया है। आवेदन आधिकारिक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (www.startupindia.gov.in) के माध्यम से 27 अक्टूबर 2026 को खुल गए हैं और 20 नवंबर 2026 तक खुले रहेंगे। एनएसए 6.0 के तहत 20 क्षेत्रवार (सेक्टोरल) श्रेणियों और तीन विशेष पुरस्कार श्रेणियों में स्टार्टअप को सम्मानित किया जाएगा; इस संस्करण में 12 नई क्षेत्रवार श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं, जिनमें बायोमैन्युफैक्चरिंग; रक्षा और सुरक्षा; इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण; महासागर और नीली अर्थव्यवस्था; तथा स्पेस-टेक, ड्रोन और एयरोस्पेस शामिल हैं। तीन विशेष पुरस्कार श्रेणियाँ हैं - वुमन-लेड स्टार्टअप ऑफ द ईयर (वर्ष का महिला-नेतृत्व वाला स्टार्टअप), नॉर्थ-ईस्ट स्टार्टअप एक्सीलेंस (पूर्वोत्तर स्टार्टअप उत्कृष्टता) और पहली बार शुरू किया गया स्टूडेंट इनोवेटर / एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर (छात्र नवप्रवर्तक / आकांक्षी उद्यमी) पुरस्कार, जिसका उद्देश्य सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। 20 क्षेत्रवार श्रेणियों और स्टार्टअप-केंद्रित दो विशेष श्रेणियों में विजेता स्टार्टअप लागू पुरस्कार दिशानिर्देशों के अधीन प्रति श्रेणी ₹25 लाख के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे, जबकि छात्र नवप्रवर्तक / आकांक्षी उद्यमी पुरस्कार में चार उप-श्रेणियों में कुल ₹25 लाख की पुरस्कार राशि होगी। वर्ष 2026 में जनवरी 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार इसके तहत एक प्रमुख पहल के रूप में उभरे हैं। नकद पुरस्कार के अलावा ये पुरस्कार मार्गदर्शन (मेंटरशिप), निवेशकों से जुड़ाव, बाज़ार तक पहुँच, उद्योग साझेदारी और पहचान बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, और एनएसए 6.0 का उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों के उभरते उद्यमशीलता इकोसिस्टम सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329132

14 संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम् मिशन के तहत भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Ministry of Culture signs an MoU with the Bibliothèque nationale de France under the Gyan Bharatam Mission to strengthen the preservation of India's manuscript heritage

SSC • Railway • General

संस्कृति मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि पांडुलिपियों और दस्तावेजी विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को मज़बूत करने के लिए ज्ञान भारतम् मिशन के तहत 26 अक्टूबर 2026 को पेरिस में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस (बीएनएफ) (फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान-प्रदान किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और बीएनएफ के अध्यक्ष गाइल्स पेकौट ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय (ज्ञान भारतम् के माध्यम से), नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय और बीएनएफ शामिल हैं, और यह पांच प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा तैयार करती है: डिजिटलीकरण; राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी पर साझाकरण (क्रॉस-शेयरिंग); प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान; संरक्षण; और अनुसंधान एवं विकास। संस्कृति मंत्रालय और बीएनएफ मिलकर बीएनएफ के पास मौजूद भारतीय मूल की पांडुलिपियों एवं संग्रहों की पहचान करेंगे और उनका डिजिटलीकरण करेंगे, और समझौता ज्ञापन में डिजिटलीकरण एवं संरक्षण तकनीकों, कैटलॉगिंग संबंधी मानकों, भारतीय लिपियों के लिए ओसीआर/एचटीआर उपकरणों, डिजिटल मानविकी तथा पांडुलिपि संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता और ज्ञान के आदान-प्रदान का भी प्रावधान है; इस साझेदारी के तहत संयुक्त कार्यशालाओं, क्षमता-विकास कार्यक्रमों, शोध संबंधी पहलों, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों और विद्वानों एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की योजना भी बनाई गई है। ज्ञान भारतम् मिशन संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जो भारत की पांडुलिपि विरासत की पहचान, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद, शोध और प्रसार के प्रति समर्पित है; इसकी राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी को भारत और दुनिया भर में मौजूद भारतीय मूल की पांडुलिपियों और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के एक सुरक्षित डिजिटल भंडार के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो शोध और अध्ययन के लिए व्यवस्थित, अनुमति-आधारित पहुंच प्रदान करे। मंत्रालय ने इस साझेदारी को भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, अध्ययन और व्यापक प्रसार के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329163

15 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत 'सृष्टि' (यार्ड 1283) का जलावतरण

Next Generation Offshore Patrol Vessel 'Srishti' (Yard 1283) launched at Goa Shipyard Limited, Goa

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गोवा में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) 'यार्ड 1283 (सृष्टि)' का जलावतरण श्रीमती संदीपा सहाय द्वारा किया गया; इस अवसर पर सचिव (रक्षा वित्त) विश्वजीत सहाय उपस्थित थे। यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना की समृद्ध परंपराओं एवं मूल्यों को दर्शाता था, और इसमें भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और जीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित ये जहाज समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) तथा समुद्री डकैती-रोधी अभियानों जैसे बहु-आयामी अभियानों के लिए मौजूदा ओपीवी/एनओपीवी की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, और एनजीओपीवी का निर्माण एक साथ दो शिपयार्ड - जीएसएल, गोवा और जीआरएसई, कोलकाता - में किया जा रहा है। इन जहाजों के नाम भारत की समृद्ध विरासत से लिए गए हैं, और इस जहाज का नाम 'सृष्टि' रखा गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है 'रचना' या 'निर्माण करने की क्रिया'। इस अवसर पर विश्वजीत सहाय ने स्वदेशीकरण पर सरकार के ज़ोर और अर्थव्यवस्था पर इसके गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट) को रेखांकित किया, जिसमें जीडीपी वृद्धि में इसका योगदान और घरेलू औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास शामिल है; उन्होंने इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तीनों सेनाओं, विशेष रूप से भारतीय नौसेना, की सराहना की और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के सरकार के विज़न को साकार करने में योगदान के लिए जीएसएल को बधाई दी। मंत्रालय के अनुसार यह जलावतरण स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' तथा 'मेक इन इंडिया' पहल के विज़न के अनुरूप है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329197

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 27 अक्टूबर 2026 से जिसके लिए आवेदन खुल रहे हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के उस 6वें संस्करण (एनएसए 6.0) में कौन-सी विशेष पुरस्कार श्रेणी पहली बार शुरू की गई है?

(A) छात्र नवप्रवर्तक / आकांक्षी उद्यमी
(B) ज़मीनी नवप्रवर्तक / ग्रामीण उद्यमिता
(C) पूर्वोत्तर स्टार्टअप उत्कृष्टता
(D) वर्ष का महिला-नेतृत्व वाला स्टार्टअप

प्र.2 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों (एनजीओपीवी), जिनमें से एक 'सृष्टि' (यार्ड 1283) का 27 अक्टूबर 2026 को जलावतरण किया गया, का निर्माण एक साथ किन दो शिपयार्ड में किया जा रहा है?

(A) जीएसएल, गोवा और जीआरएसई, कोलकाता
(B) एमडीएल, मुंबई और एचएसएल, विशाखापत्तनम
(C) जीएसएल, गोवा और एमडीएल, मुंबई
(D) सीएसएल, कोच्चि और जीआरएसई, कोलकाता

प्र.3 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए शुरू किए गए रियायती स्थानीय पास के तहत, नगर पालिका या स्थानीय शहर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए वार्षिक शुल्क कितना है?

(A) 2,500 रुपये
(B) 3,000 रुपये
(C) 1,500 रुपये
(D) 1,000 रुपये

प्र.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 का विषय क्या है?

(A) राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति
(B) एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत
(C) सत्यनिष्ठा से समृद्धि
(D) सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी

प्र.5 चक्रवाती तूफ़ान 'अर्नब' (ARNAB) की तैयारियों की समीक्षा के लिए 26 अक्टूबर 2026 को हुई राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की बैठक की अध्यक्षता किसने की?

(A) कैबिनेट सचिव
(B) केंद्रीय गृह सचिव
(C) NDRF के महानिदेशक
(D) IMD के महानिदेशक

उत्तर: 1-(A) 2-(A) 3-(C) 4-(C) 5-(A)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।